(b) Certain time-limit for disposal of cases has been fixed under the Consumer Protection Act, 1986. Cases which do not require testing, have to be disposed of within 3 months and cases which require testing have to be decided within 5 months.

(c) and (d) Piling up of cases in consumer courts is due to a number of reasons like frequent adjournments, lack of proper infrastructure, etc. The Consumer Protection Act, 1986 as amended in 1993 empowers the State Govemments to set up additional District Forum(s) for disposal of cases. The responsibility of setting up of additional District Forum(s) lies with the State Govemments. The Central Government has also agreed to give a one-time financial assistance of Rs.61 crores to the State Govemments in four half-yearly instalments to strengthen the infrastructure of the consumer courts.

महिला श्रमिकों के संरक्षण हेतु विधान

781. **श्री अनन्तराम जायसवाल**:

श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू वस्तुओं के उत्पादन में कार्यरत महिला श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने हुते कोई घेरक पुरःस्थापित करने का विचार रखती हैं;

(ख) यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या हैं और सरकार संबंध में कब तक और किस प्रकार का निर्णय लेने विचार रखती हैं?

श्रम मंत्री (**श्री पी.ए.संगमा**): (क) "घरेलू काम" के उत्पादन में कार्यरत महिला श्रमिकों को भी प्रदान करने हेतु कोई विधेयक लाने के लिए इस कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Spread of byssinosis among workers in Textile Industry

782. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:
DR. BAPU KALDATE:
SHRI AJIT P.K. JOGI:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the labourers working in the textile industry are suffering from a particular disease called bysssinosis;

(b) if so, the details thereof, State-wise; and

(c) the action taken by Government in this regard and measures taken for protecting the labourers from acquiring the said disease?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pending residual work with coal controller

783. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the status and details of the pending residual work of World Bank Loan relating to prenationalisation period being dealt with by the Coal Controller;

(b) what is being done to expedite this work; and

(c) by what time this work will continue and what is its relativance now?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) According to information furnished by Coal Controller, securities amounting to Rs. 11.22 lakhs were secured from 185 coal companeis who participated in World Bank Loan scheme. A sum of Rs. 8.17 lakhs has been released to 113 coal companies. Due to violation of the terms and conditions of the loan scheme, securities worth Rs. 1.74 lakhs pertaining to 28 coal companies were forfeited. 44 coal companies have not yet claimed the release of securities worth Rs. 1.31 lakhs.

Two applications for release of securities were received in the year 1992-93. Their claims have not been accepted by the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Branch Secretariat, Calcutta, whose approval is necessary.

(b) and (c) For receiving claims from different erstwhile private coal companies, the matter was taken up with different associations in the year 1978-79. Unless the erstwhile private coal companies come forward with their claims, no further action can be taken.

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अर्जित किया गया लाभ और उसके द्वारा किया गया निर्यात

784.**श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष-वार कितना-कितना शुद्व लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या अर्जित किया गया लाभ अपेक्षित था और मूलभूत रूप से उसके क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कोल इंडिया ने कितना निर्यात किया;

(घ) इन वर्षो के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले की क्या बाजार दर और निर्यात दर निर्धारित की थीं;और

(ड़) वर्ष 1995-96 के दौरान कोल इंडिया लि.ने कोयले के निर्यात के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं,और उन्हें पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं इससे अनुमानत: और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) कोल इंडिया लि.द्वारा 1991-92 से 1993-94 तक की 3 वर्षो की अवधि के दौरान अर्जित किए गए लाभ को नीचे दर्शाया गया हैं :-

(करोड़ रू.में)

19991-92	167.07
1992-93	291.27
1993-94	400.32

वर्ष 1994-95 के लिए लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं ।

(ख) कोल इंडिया लि.का 1991-92, 1992-93,1993-94 और 1994-95 के दौरान बजटीय लाभ /हानि नीचे दी गई हैं:-

लाभ(+)/हानि(-)

1991-92	(-)87
1992-93	(+)273
1993-94	(+)250
1994-95	(+)410

(ग) कोल इंडिया लि.ने 3 वर्षो की अवधि दौरान निम्नलिखित मात्रा में कोयले का निर्यात हैं :-